

समक्ष एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायमूर्ति और एस.एस. सोढ़ी, न्यायमूर्ति ।

रविंदर सिंह कालेका और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी।

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 375

01 नवंबर 1983

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 26-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (XXXI ओजे 1950)-धारा 78-अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम XXXIII 1956)-धारा 11-धारा 78 की संवैधानिकता और उसके तहत दिए गए पुरस्कार की वैधता को रिट में चुनौती दी गई निजी पक्षों द्वारा कार्यवाही - ऐसी शुद्धियां - क्या अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा 11 के तहत रिट याचिका को बनाए रखने का अधिकार है - क्या याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक है - अंतर-राज्य जल विवाद से संबंधित विवाद - राज्यों के बीच दिए गए निर्णय को केवल प्रभावित राज्यों द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है।

अभिनिर्धारित कि यह स्पष्ट है कि एक नए न्यायशास्त्र ने अब लोकस स्टैंडी के संबंध में इस पारंपरिक नियम को कमजोर कर दिया है कि एक रिट याचिकाकर्ता जिसने खुद कानूनी चोट झेली है, वह न्यायिक निवारण की मांग कर सकता है। लोकस स्टैंडी की अवधारणा का विस्तृत दायरा अब सार्वजनिक गलती या नागरिक को लगी सार्वजनिक चोट पर समान रूप से लागू किया गया है। अब यह माना जाना चाहिए कि जब भी राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के किसी कार्य या चूक के कारण कोई सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक चोट होती है, जो संविधान या कानून के विपरीत है, तो जनता का कोई भी सदस्य सद्भावना से काम कर सकता है और पर्याप्त हित रख सकता है। ऐसी सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए कार्रवाई बनाए रखें। खड़े होने का सख्त नियम जो इस बात पर जोर देता है कि केवल वही व्यक्ति जिसे विशिष्ट कानूनी चोट लगी है, न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई कर सकता है, उसे शिथिल कर दिया गया है और एक व्यापक नियम विकसित किया गया है जो जनता के किसी भी सदस्य को खड़ा करता है जो केवल व्यस्त निकाय नहीं है या एक हस्तक्षेप करने वाला इंटरऑपर लेकिन जिसकी आगे बढ़ने में पर्याप्त रुचि हो। इसके अलावा पर्याप्त

हित रखने वाला जनता का कोई भी सदस्य सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन या संविधान या कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक चोट के लिए न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई कर सकता है और ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने और ऐसे संवैधानिक या कानून के पालन की मांग कर सकता है। कानूनी प्रावधान। यह कानून के शासन को बनाए रखने, संवैधानिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है, इसलिए, जहां पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 की संवैधानिकता और उसके तहत दिए गए पुरस्कार को एक निजी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो न्यायिक मांग कर रहा है सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न कथित सार्वजनिक गलती के निवारण के लिए भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार है।

(पैरा 7 और 8)

अभिनिर्धारित कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 11 के प्रावधानों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बार किसी भी जल विवाद के संबंध में संचालित होता है जिसे इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। जहां नदियों से संबंधित किसी भी विवाद के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई संदर्भ अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किसी भी न्यायाधिकरण को नहीं भेजा गया है, धारा 11 आकर्षित नहीं होती है।

(पैरा 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट याचिका;

और

1966 के अधिनियम 31 (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम) और उसकी धारा 78 के मामले में;

और

1966 के अधिनियम 31 की धारा 78(1) के तहत भारत सरकार (कृषि और सिंचाई मंत्रालय) द्वारा 24 मार्च, 1976 को जारी अधिसूचना के मामले में;

और

31 दिसंबर, 1981 के समझौते के मामले में, जैसा कि प्रेस (अनुलग्नक पी-2) में बताया गया है, जो कि 24 मार्च, 1976 की उपरोक्त अधिसूचना के भिन्न रूप में किया गया था; और

भारत सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच रावी-ब्यास जल आवंटन के मामले में, प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करे: -

(ए) पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास और रावी) के जल आवंटन को लेकर केंद्र सरकार के 1955 के फैसले को खराब और अप्रभावी घोषित करना; और भारत संघ और राजस्थान राज्य को इसे आगे लागू करने से रोकना-

(बी) यह घोषणा करते हुए कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधान जहां तक उनका उद्देश्य केंद्र सरकार को ब्यास परियोजना नदियों के पानी और ऐसे पानी के आवंटन या वितरण के संबंध में निर्धारण करने के लिए अधिकृत करना है संसद की क्षमता का उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 246(3) का उल्लंघन;

(सी) यह घोषणा करते हुए कि 24 मार्च 1976 की अधिसूचना (अनुलग्नक पीए) में निहित आदेश अमान्य और शून्य हैं;

(डी) पंजाब हरियाणा और राजस्थान आदि राज्यों के बीच दिनांक 31 दिसंबर, 1981 (अनुलग्नक पी 2) के समझौते को खराब घोषित करना;

उपरोक्त प्रार्थना के विकल्प में याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि यह घोषित किया जाए कि ब्यास परियोजना की योजना में हरियाणा को 0.9 एमएएफ से अधिक पानी के आवंटन की सीमा अमान्य और कानून के विपरीत है। केंद्र सरकार और हरियाणा राज्य को ब्यास परियोजना के परिणामस्वरूप 0.9 एमएएफ से अधिक पानी के आवंटन के संबंध में पंजाब राज्य के खिलाफ किसी भी दावे को लागू करने से एक आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को ऐसी अतिरिक्त और अन्य राहतें प्रदान की जाएं जो इस भयानक न्यायालय को उचित, उचित और सुविधाजनक लगे ताकि याचिकाकर्ताओं के कानूनी अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

याचिकाकर्ता के लिए एम.एस. खैरा, वकील, (एच.एस. भुल्लर और बी.एस. मल्होत्रा, उनके साथ)।

जे.एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमर जीत चौधरी के साथ, भारत संघ के लिए।

हरभगवान सिंह, ए.जी., हरियाणा राज्य के लिए।

ए.एस. संधू, अतिरिक्त ए.जी., पंजाब राज्य के लिए।

अशोक भान, वरिष्ठ वकील, राजस्थान राज्य के वकील मुकुल मुदगेल के साथ

### निर्णय

एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायमूर्ति।

(1) न्यायालय की दहलीज पर, पांच मामलों के इस सेट में उत्तरदाताओं की ओर से प्रवेश करने वाले 23 रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र पर ही हमला किया गया है। इस प्रस्ताव आदेश के सीमित

उद्देश्य के लिए, तथ्यों को किसी भी बड़े विवरण में विज्ञापित करना अनावश्यक लगता है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि इन रिट याचिकाओं में अन्य बातों के साथ-साथ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण संवैधानिक और यहां तक कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं: -

(i) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 की संवैधानिक वैधता और सूची-2 की विधायी प्रविष्टि-17 और सूची-1 की प्रविष्टि-56 के संदर्भ में इसे अधिनियमित करने की संसद की विधायी क्षमता संविधान की सातवीं अनुसूची;

(ii) यह मानते हुए भी कि उपरोक्त की धारा 78 अधिकारेतर है, प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया पुरस्कार और केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च 1976 के राजपत्र में अधिसूचित, उपरोक्त धारा 78 के तहत माना जाता है, फिर भी अधिकारातीत, अवैध और है यह शून्य है कि 31 दिसंबर, 1981 को प्रधान मंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच हुआ समझौता, उपरोक्त धारा 78 के दायरे और दायरे से समान रूप से परे है;

(iii) कि किसी भी मामले में धारा 78(1) और उसके प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग उचित संवैधानिक रूप में नहीं है;

(iv) इस धारणा पर भी कि 31 दिसंबर, 1981 का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का समझौता प्रकृति में संविदात्मक है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और है , इसलिए, शून्य और अप्रवर्तनीय ;

(v) राजस्थान राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अर्थ के तहत उत्तराधिकारी राज्य नहीं होने के कारण और रावी और ब्यास नदियों के संबंध में सह-तटीय राज्य नहीं होने के कारण, एक होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य था। कथित समझौते का पक्ष; और

(vi) जहां तक जल स्रोतों के बंटवारे की बात है, उत्तराधिकारी राज्यों के बीच संपत्तियों के बंटवारे से संबंधित उपरोक्त धारा 78, ब्यास परियोजना रिपोर्ट तक पूरी हो चुकी थी और समाप्त हो चुकी थी।

(2) मुख्य कानूनी मुद्दों के अलावा, यहां जो बात काफी हद तक दांव पर है, वह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच रावी और ब्यास के पानी का आवंटन है। हालाँकि यहाँ चुनौती पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 78 के तहत 24 मार्च 1976 को अधिसूचित प्रधान मंत्री के पुरस्कार पर वापस जाती है, बाद में राज्यों के बीच समझौता हुआ। 31 दिसंबर, 1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर अधिक स्पष्ट रूप से हमला किया गया है।

(3) अब हमारे सामने यह विवादित नहीं था कि लोकस स्टैंडी के मुद्दे का फैसला मुख्य रूप से रिट याचिकाओं में दलीलों और बुनियादी लिस और उनमें उठाए गए प्राथमिक मुद्दों पर किया जाना है। इसमें सबसे पहले अधिनियम की धारा 78 की संवैधानिकता पर ही घातक हमला किया गया है। वास्तव में, इस धारा को अधिनियमित करने की संसद की क्षमता को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 56 से परे और पूरी तरह से सूची-2 की प्रविष्टि 17 के भीतर होने के कारण चुनौती दी गई है। तथ्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय वास्तव में अधिनियम की धारा 78 को अधिनियमित करने के लिए संवैधानिकता और संसद की क्षमता के मुद्दे को उठाने

के लिए एकमात्र मंच नहीं तो उचित मंच है। वास्तव में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बहुत निष्पक्षता से इस स्थिति का गंभीरता से खंडन नहीं किया। यह कुछ हद तक स्पष्ट प्रतीत होता है कि आम तौर पर कोई कानूनी बाधा नहीं उठाई जा सकती है और हमारे सामने कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं रखा जा सकता है जो रिट याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 78 की वैधता को मुद्दा बनाने से रोक सके। इसलिए, यह इस प्रकार है कि यदि अधिनियम की धारा 78 लागू होती है या परिस्थितियों में लागू होती है, तो रिट क्षेत्राधिकार ऐसे उपाय की तलाश के लिए उचित मंच है।

(4) चूँकि यहाँ तर्क अधिनियम की धारा 78 के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए उसके प्रासंगिक भाग को उद्धृत करना उपयुक्त है: -

"भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं के संबंध में अधिकार और दायित्व: -

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन धारा 79 और 80 के प्रावधानों के अधीन, भाखड़ा-नांगल परियोजना और ब्यास परियोजना के संबंध में मौजूदा पंजाब राज्य के सभी अधिकार और दायित्व नियत दिन पर होंगे। उत्तराधिकारी राज्यों के अधिकार और दायित्व ऐसे अनुपात में, जो तय किया जा सकता है, और ऐसे समायोजनों के अधीन, जो केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद उक्त राज्यों द्वारा किए गए समझौते द्वारा या, यदि नहीं, तो किए जा सकते हैं। ऐसा समझौता नियत दिन के दो वर्षों के भीतर किया जाता है, जैसा कि केंद्र सरकार परियोजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा निर्धारित कर सकती है: बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया आदेश किसी भी बाद के समझौते द्वारा भिन्न हो सकता है। केंद्र सरकार के परामर्श के बाद उत्तराधिकारी राज्य।

(5) उपरोक्त प्रावधान की स्पष्ट भाषा के सामने, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-हरियाणा राज्य की ओर से लगभग निराशा का एक तर्क उठाया गया था कि उपरोक्त धारा के प्रावधान विवाद के लिए बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे। और इसलिए, इसकी संवैधानिकता के लिए चुनौती कोई बड़ी प्रासंगिकता नहीं थी। इस रुख पर केवल गौर किया जाना चाहिए और खारिज किया जाना चाहिए। यह सामान्य आधार है कि प्रधान मंत्री का पुरस्कार, जिसे बाद में 24 मार्च, 1976 को अधिसूचित किया गया था और जो विवाद की आधारशिला प्रतीत होता है, अधिनियम की धारा 78 के तहत है। उक्त अधिसूचना का एक मात्र संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि इसे स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 78(1) के तहत जारी करने की मांग की गई है और उक्त प्रावधान के पैरामीटर के भीतर शामिल है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह अधिसूचना 'चुनौती' के तहत प्राथमिक कृत्यों में से एक है। इसलिए, यह प्रचार करना कि यहां अधिनियम की धारा 78 लागू नहीं होती है, स्पष्ट रूप से अस्थिर प्रतीत होता है।

(6) हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने तब यह तर्क देने का प्रयास किया था कि प्रधान मंत्री की उपस्थिति में 31 दिसंबर, 1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के समझौते ने अधिनियम की धारा 78 के तहत पहले की अधिसूचना को खत्म कर दिया था। और इसलिए, बाद वाला अब इस मुद्दे के लिए अप्रासंगिक हो गया है। यह सहायक विवाद हमारे पक्ष

में नहीं है। अधिनियम की धारा 78 की उप-धारा (1) को पढ़ने से पता चलता है कि उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समझौते के अभाव में केंद्र सरकार को भाखड़ा-नांगल में प्रत्येक राज्य के अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करने का अधिकार था। ब्यास परियोजना. यह स्पष्ट रूप से उक्त प्रावधान के तहत था कि प्रधान मंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया था और बाद में 24 मार्च 1976 को विधिवत अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना के शुरुआती भाग में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह अधिनियम की धारा 78(1) के तहत था। . अब एक बार ऐसा है, तो इसका मतलब यह होगा कि अगला समझौता पूरी तरह से उपधारा (1) के प्रावधानों के दायरे में आता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों ने बाद के समझौते द्वारा पिछले पुरस्कार को बदल दिया था।

उनके द्वारा प्रवेश किया गया। माना कि इस अधिनियम के तहत पंजाब और हरियाणा उत्तराधिकारी राज्य थे और यह बदलाव भी केंद्र सरकार के परामर्श के बाद किया गया था। नतीजतन, यह अधिनियम की धारा 78(1) के प्रावधान के समान रूप से संदर्भित होगा। इसलिए, इन रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों से निपटने के दौरान उक्त धारा सीधे तौर पर और काफी हद तक विचार के दायरे में आती है और इसके अधिकार के सवाल को टाला या दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि शुरुआत में ही देखा जा चुका है, यह सामान्य आधार है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करने वाला यह न्यायालय, निश्चित रूप से इसके लिए एक उपयुक्त मंच है।

(7) एक बार फिर, लोकस स्टैंडी के सवाल पर उत्तरदाताओं का कुछ हद तक कड़ा रुख यह था कि रिट याचिकाकर्ताओं को निजी व्यक्ति या पक्ष होने के नाते न्यायिक निवारण के लिए अदालतों में जाने से रोक दिया गया था। यह तर्क दिया गया कि इस तरह का उपाय केवल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों द्वारा ही खोजा जा सकता है और उनमें से किसी ने भी प्रधान मंत्री के मूल पुरस्कार और न ही मुख्यमंत्रियों के बाद के समझौते से व्यथित महसूस किया। यह उत्तरदाताओं का मामला था कि चूंकि विवाद अंतर-राज्यीय नदियों से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के किसी भी सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत चोट या सार्वजनिक गलती के लिए हमला करने में सक्षम बनाया जा सके। विकल्प में, यह तर्क दिया गया कि नदी बेसिन के पानी का आवंटन न होने और इसके परिणामस्वरूप कृषि प्रयोजन के लिए पानी कम होने से रिट याचिकाकर्ताओं को निजी क्षति बहुत कम थी।

(8) यदि लोकस स्टैंडी के संबंध में पारंपरिक नियम, कि एक रिट याचिकाकर्ता जिसने स्वयं कानूनी चोट का सामना किया है, वह न्यायिक निवारण की मांग कर सकता है, तो उत्तरदाताओं के उपरोक्त रुख का उन्हें लाभ मिल सकता था, फिर भी मैदान में बने रहते। हालाँकि, यह स्पष्ट से अधिक है कि एक नए न्यायशास्त्र ने अब इस पारंपरिक नियम को छोटा कर दिया है, जो लोकस स्टैंडी की अवधारणा के व्यापक क्षितिज को देखते हुए पुरातन हो गया है और इसे सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक चोट पर समान रूप से लागू किया गया है। नागरिक। इस आदेश के प्रयोजन के लिए, एस. पी. गुप्ता और अन्य बनाम भारत के राष्ट्रपति मामले में सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा हाल ही में आधिकारिक प्रतिपादन या इसकी पुनरावृत्ति के मद्देनजर इस क्षेत्र में कानून

के विकास का पता लगाना अनावश्यक है। अन्य (1). जहाँ तक पहले उदाहरण का संबंध है, राम किशोर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2), मगनभाई ईश्वरभाई पटेल बनाम भारत संघ और अन्य (3), अखिल में लोकस स्टैंडी के दायरे के क्रमिक विस्तार के लिए निर्देशात्मक रूप से संदर्भ दिया जा सकता है। भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ और अन्य। (4) और, उर्वरक निगम कामगार यूनियन (पंजीकृत) सिंदरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (5)। एस. पी. गुप्ता के मामले (सुप्रा) में, उनके आधिपत्य ने सबसे पहले लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम के लंबे इतिहास का पता लगाया और उसमें छूट और उसके प्रभाव पर ध्यान दिया।

(1) एआईआर 1982 एस.सी. 149।

(2) एआईआर 1966 एस.सी. 644।

(3) एआईआर 1969 एस.सी. 788।

(4) एआईआर 1981 एस.सी. 298।

(5) एआईआर 1981 एस.सी. 344।

निम्नलिखित शर्तों में विस्तार: -

"इसलिए कई निर्णयों में न्यायालयों द्वारा यह विचार किया गया है कि जब भी कोई सार्वजनिक गलती होती है" या राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के किसी कार्य या चूक के कारण सार्वजनिक चोट लगती है जो संविधान या कानून के विपरीत है, तो इसका कोई भी सदस्य जनता ईमानदारी से काम कर रही है और पर्याप्त रुचि रखते हुए ऐसी सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए कार्रवाई कर सकती है। खड़े होने का सख्त नियम जो इस बात पर जोर देता है कि केवल वही व्यक्ति जिसे विशिष्ट कानूनी चोट लगी है, न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई कर सकता है, उसे शिथिल कर दिया गया है और एक व्यापक नियम विकसित किया गया है जो जनता के किसी भी सदस्य को खड़ा करता है ^ जो केवल व्यस्त नहीं है- निकाय या हस्तक्षेप करने वाला हस्तक्षेपकर्ता है लेकिन जिसकी कार्यवाही में पर्याप्त रुचि है।"

इसके बाद, उनका आधिपत्य इस प्रकार समाप्त हुआ: -

"इसलिए, हम यह मानेंगे कि" पर्याप्त हित रखने वाला जनता का कोई भी सदस्य सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन या संविधान या कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक चोट के लिए न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई कर सकता है और प्रवर्तन की मांग कर सकता है। ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य और ऐसे संवैधानिक या कानूनी प्रावधान का पालन। कानून का शासन बनाए रखने, न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति की गति को तेज करने के लिए यह नितांत आवश्यक है।" "

और आगे अत्यधिक सख्त पारंपरिक नियम के अनुरूप होने के विनाशकारी परिणामों को इंगित किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

"यदि कोई भी ऐसे सार्वजनिक गलत या सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि यह राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अपनी शक्ति के दायरे से परे दण्डमुक्ति के साथ कार्य करने के लिए खुला होगा। या उसके स्वामित्व वाले किसी सार्वजनिक कर्तव्य की शाखा में। अदालतें ऐसी स्थिति का

सामना नहीं कर सकती हैं जहां कानून का पालन उसके द्वारा बंधे प्राधिकारी की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, और कानून का उल्लंघन होने पर कोई निवारण नहीं किया जाता है।

उपरोक्त आधिकारिक व्याख्या के आलोक में, अब यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यहां रिट याचिकाकर्ता, जो सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न एक कथित सार्वजनिक गलती के लिए न्यायिक निवारण की मांग कर रहे हैं, पूरी तरह से नियम के अंतर्गत निर्धारित हैं।

(9) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्षता में, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और विशेष रूप से उसकी धारा 11 से कुछ भरण-पोषण की मांग की। यह तर्क दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदियों या लिवर घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने और ऐसे विशेष विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाने के लिए अधिकृत करता है। यह प्रस्तुत किया गया कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 को इस प्रावधान की छत्रछाया में अधिनियमित किया गया है और परिणामस्वरूप संवैधानिकता के मुद्दे सहित सभी मामलों में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से बाहर हो गया है।

(10) अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 11 को उद्धृत करना उपयुक्त है, जिस पर विशेष निर्भरता रखी गई है: -

"सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की वर्जना:

किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास किसी भी जल विवाद के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा, जिसे इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों के पक्ष में सब कुछ मानते हुए, बार किसी भी जल विवाद के संबंध में कार्य करता है जिसे इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल को भेजा जा सकता है। माना जाता है कि, रावी और ब्यास नदियों से संबंधित किसी भी विवाद के संबंध में किसी भी स्तर पर तत्कालीन अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किसी भी न्यायाधिकरण को कोई संदर्भ नहीं भेजा गया है। इसलिए, हम यह देखने में असमर्थ हैं कि उपरोक्त उद्धृत कैसे किया गया है सेक्शन 11 किसी भी तरह से वर्तमान मामले की ओर आकर्षित है। समान रूप से, यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 3 के आधार पर उपरोक्त कानून केवल राज्य सरकारों को विवाद उठाने और ट्रिब्यूनल के संदर्भ में शिकायत करने का अधिकार प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत नागरिक को उसके सार्वजनिक अधिकार की सुरक्षा या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए कोई प्रक्रिया या उपाय प्रदान नहीं करता है। विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा, इस तर्क की चरम सीमा तक चले गए थे कि उपरोक्त धारा 11 प्रावधानों की संवैधानिकता के संबंध में भी उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार पर रोक लगा देगी। हालाँकि, इस गंजे दावे के लिए न तो सिद्धांत और न ही मिसाल का हवाला दिया जा सकता है। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम उपरोक्त धारा 11 को पढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, क्योंकि



हम स्थिति से आकर्षित हैं या उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम हैं, जो प्रतिष्ठित रिट जारी करने के स्तंभ बन गए हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए उपाय या कानून की संवैधानिकता की न्यायिक समीक्षा या सातवीं अनुसूची की संबंधित प्रविष्टियों के तहत कानून बनाने के लिए विधायिकाओं की क्षमता को रोकने के लिए। परिणामस्वरूप, उपरोक्त धारा 11 पर उत्तरदाताओं का तर्क \*यहां तक कि अधिनियम की धारा 78 पर हमला करने के रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकार को भी रोक देगा, हमें पूरी तरह से अस्थिर प्रतीत होता है।

(11) हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अंतर-राज्य नदियों और उनसे संबंधित विवादों के संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया था कि न तो रावी नदी और न ही ब्यास नदी को राजस्थान राज्य के लिए अंतर-राज्य नदी माना जा सकता है। स्वीकृत भौगोलिक स्थिति के कारण, वे किसी भी स्तर पर प्रवाहित नहीं होते हैं और यहाँ तक कि इसके क्षेत्र को छूते भी नहीं हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रयोजन के लिए, यहां तक कि एक राज्य के लिए उपलब्ध उपचार भी केवल विवादित पक्षों के लिए एक अंतर-राज्य नदी के मामले में ही लागू किए जा सकते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की विस्तृत और आधिकारिक रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियों पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि राजस्थान नर्मदा जल के संबंध में विवाद के लिए एक नदी तटीय क्षेत्र नहीं है: -

"इसलिए, हमारा निष्कर्ष यह है कि राजस्थान राज्य इस आधार पर नर्मदा बेसिन के पानी के किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है कि राजस्थान राज्य सहवर्ती राज्य नहीं है या इसका कोई भी हिस्सा: इसका क्षेत्र बेसिन में स्थित नहीं है नर्मदा नदी। हम यह भी मानते हैं कि 1956 अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायनिर्णयन के लिए राजस्थान की शिकायत को इस न्यायाधिकरण को संदर्भित करने में केंद्र सरकार संख्या 10/1/69-डब्ल्यूडी दिनांक 16 अक्टूबर 1969 का संदर्भ 1956 अधिनियम मुद्दे 2 का उल्लंघन है। (बी) और 3 के अनुसार उत्तर दिए गए हैं।

(12) ऊपर दर्ज विस्तृत कारणों के लिए, हमें इस निष्कर्ष की कोई गुंजाइश नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास वास्तव में वर्तमान रिट याचिकाओं को बनाए रखने का अपेक्षित अधिकार है और उन्हें सीमा पर रोक नहीं जा सकता है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि न केवल वैधानिक प्रावधानों की संवैधानिकता के मामले, बल्कि काफी महत्व के मुद्दे भी उठाए जाते हैं, जिन पर निस्संदेह सावधानीपूर्वक और आधिकारिक विचार की आवश्यकता होती है। हम तदनुसार इन रिट याचिकाओं को पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार करते हैं।

(13) इनमें से कुछ रिट याचिकाएँ जनवरी, 1982 में इस न्यायालय में दायर की गई थीं और पार्टियों के वकीलों के बार-बार और संयुक्त अनुरोध पर प्रस्ताव चरण में इस उम्मीद में लंबित रहीं कि इस मुद्दे को पारस्परिक रूप से सुलझा लिया जाएगा। अदालत। हालाँकि, हम मानते हैं कि अब इसमें कोई और देरी अनुचित होगी और इसलिए, निर्देश देते हैं कि जो मामले पूरे हो गए हैं, उन्हें 15 नवंबर, 1983 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन कुमार सिंह  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
(Trainee Judicial Officer)  
नूँह, हरियाणा